दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जुलाई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा को मिला 'एमएसएमई नेशनल अवार्ड' में तीसरा स्थान 3
- हरियाणा 'स्टेट ईंज ऑफ डूईंग बिजनेस' में शीर्ष राज्यों में शामिल 3
- दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में मिलेगा चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण 4
- हरियाणा में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों के वेतन में वृद्धि का फैसला 4
- दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों के किसानों को मिलेगा लाभ 5
- हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति, 2022-25 5
- 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में हरियाणा सत्रहवें स्थान पर 6
- पशुओं के नस्ली विकास के लिये हरियाणा ब्राज़ील के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा 6
- चरखी दादरी को मिली करीब 1100 करोड़ रुपए की सौगात 7
- पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन करेगी हरियाणा सरकार 7
- हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2022 में स्वर्ण सहित जीते 3 पदक 8
- पैक्स की कार्यप्रणाली को किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड 8
- एचसीएस प्री की परीक्षा में चार के बजाय पाँच विकल्प होंगे 9
- हरियाणा सरकार ने किया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9
- रोहतक में 500 एकड़ में बनेगा 'फुटवियर-लेदर' क्लस्टर 10
- ब्राज़ील के सहयोग से हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिये उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा 11
- उप-मुख्यमंत्री ने किया उचाना नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन 11
- हरियाणा मे ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ 12
- हरियाणा में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण 12
- नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल 13
- हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 13
- नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) की दोदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ 14
- परिवार पहचान-पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च 14
- 159 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं को मंज़ूरी 15
- विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 16
- प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये खोली जाएंगी 1200 लाइब्रेरी 16
- मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में किया पुलिस के 'स्मार्ट ई-बीट सिस्टम'का शुभारंभ 17
- हरियाणा ई-अधिगम टैबलेट वितरण योजना की उज्बेकिस्तान ने की सराहना 17
- हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति-2022 18
- पैक्स उपभोक्ताओं के लिये शीघ्र ही एकमुश्त योजना 19
- हरियाणा सरकार 2023 में बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल' के रूप में प्रचारित करेगी 19
- वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका 'वित्त विभाग बुलेटिन'जारी 20
- 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022' को मिली मंज़ूरी 20
- हरियाणा एसडीजी ज़िला सूचकांक-2022 जारी 20
- हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्त्वपूर्ण निर्णय 22

नोट :

हरियाणा

हरियाणा को मिला 'एमएसएमई नेशनल अवार्ड' में तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2022 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी-भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एमएसएमई के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय कार्यों हेतु देश में तीसरा स्थान पाने के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- एमएसएमई के क्षेत्र में हरियाणा देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल हैं। कार्यक्रम में हरियाणा के दो एमएसएमई को भी अवार्ड मिला है। इनमें डॉ. हरजिंद्र कौर तलवार को वुमैन कैटेगरी के स्मॉल सर्विस इंटरप्राइज में प्रथम तथा रिषभ गुप्ता को मैनुफैक्चरिंग माईक्रो इंटरप्राइज की ओवरऑल कैटेगरी में तीसरे स्थान का अवार्ड मिला है।
- इस अवसर पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के आर्थिक विकास में एमएसएमई का विशेष योगदान रहा है। प्रदेश में लगभग 9.7 लाख एमएसएमई हैं, जो कि बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई का समर्थन करने के लिये एक समर्पित विभाग 'एमएसएमई निदेशालय' की स्थापना की हुई है, इससे बाजार, प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमिकों तक पहुँच आसान हुई है।
- उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा ने 'वोकल फॉर ग्लोबल' के सिद्धांत पर चलते हुए अपनी तरह का एक प्रोग्राम 'पद्मा' शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य खंड स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढाँचा तैयार करना है।
- उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना पर जोर देने के अलावा हरियाणा अपनी तरह की पहली 'राज्य मिनी क्लस्टर योजना' भी लेकर आया है। अब तक, एमएसई-सीडीपी योजना के तहत हरियाणा से 140 करोड़ रुपए की लागत के 9 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। इसमें से भारत सरकार की ओर से 58 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।
- राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजना के तहत प्रदेश में 43 एमएसएमई कलस्टर की विभिन्न पहलें, जिनकी कीमत 119 करोड़ रुपए से अधिक है, आरंभ की गई हैं। राज्य सरकार के इन व्यापक क्लस्टर विकास प्रयासों से हरियाणा में 8,000 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

हरियाणा 'स्टेट ईंज ऑफ डूईंग बिजनेस' में शीर्ष राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टेट ईंज ऑफ डूईंग बिजनेस' के पाँचवें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल है। हरियाणा के अलावा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के प्रमोशन के लिये गठित विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) को सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन और फीडबैक के आधार पर रैंक प्रदान की है।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 की कार्ययोजना में 15 क्षेत्रों में 301 सुधार बिंदु शामिल थे। इन सुधारों के कार्यान्वयन में हरियाणा ने 99+ प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है। इसके अतिरिक्त निर्यात तैयारी सूचकांक (भूमि बंद श्रेणी)-2021 में राज्य को पहला तथा 'लॉजिस्टिक्स इज एक्रोस डिफरेंट स्टेटस सर्वे-2021' में दूसरा स्थान मिला है।

नोट :

- राज्य सरकार ने राज्य में निवेश के माहौल में सुधार के लिये कई प्रमुख कदम उठाए, जिनमें नई औद्योगिक नीति 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020' विशेष रही। इन नीति का उद्देश्य राज्य में 5 लाख नौकरियाँ पैदा करना, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपए करना है।
- राज्य में 100 राज्य-विधियों (अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों) का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिससे प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बना है।
- हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कई निवेश-प्रस्तावों, जैसे- मारुति, फाइवले, ग्रासिम पेंट्स, एटीएल बैटरीज, आरती ग्रीन टेक लिमिटेड, एंपेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनरिच एग्रो फूड प्रोडक्टस आदि ने रुचि दिखाई है।
- विजयेंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार की उद्योगों को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता के कारण ही हरियाणा की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट रेडीनेस में उत्कृष्ट रैंकिंग आई।

दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में मिलेगा चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नतियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी-पत्र जारी कर दिया। इसका लाभ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में कवर होने वाले बेंचमार्क दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार, डीसी व एसडीएम के अलावा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया है।
- 19 अप्रैल, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, लागू हुआ था, इसलिये चार प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण का लाभ 19 अप्रैल, 2017 से मिलेगा।
- पदोन्नति के मामले में ग्रुप ए, बी, सी और डी कैडर के कुल पदों में से चार प्रतिशत दिव्यांगों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे। दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, बधिर या हार्ड हियरिंग, लोकोमोटर दिव्यांगता में सेरिब्रल पॉल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) से पीड़ित व्यक्ति, लेप्रोसी क्योर्ड, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले में 1-1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- ऑटिज्म, इंटलेक्चुअल डिसएबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी और मेंटल इलनेस, बहरापन के मामले में ग्रुप ए से डी तक मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी में संयुक्त रूप से एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
- अधिसूचना के अनुसार यदि कोई विभाग दिव्यांगों के लिये आरक्षण के प्रावधान से किसी पद/संवर्ग को आंशिक रूप से या पूरी तरह से छूट देना आवश्यक समझता है तो प्रस्ताव की पूर्ण तर्कसंगत बताते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आग्रह कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों) के लिये आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है। दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों जैसी श्रेणियों के लिये आरक्षण को हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहते

हरियाणा में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों के वेतन में वृद्धि का फैसला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा राज्य के राजकीय स्कूलों में बच्चों के लिये दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों के मासिक वेतन में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा विभाग की ओर से मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों का मासिक वेतन अब दोगुना हो जाएगा, अर्थात् जुलाई माह से उन्हें 7 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि अब तक मिड-डे मील रसोइयों को वेतन 3500 रुपए प्रतिमाह मिलता था।
- विदित है कि राज्य में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 76,679 बच्चों के लिये 1697 रसोइया दोपहर का खाना बनाते हैं।

दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों के किसानों को मिलेगा लाभ

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2022 को हरियाणा सरकार दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों के लिये विशेष योजना की शुरुआत की। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिये इस नई योजना की शुरुआत की गई है।
- यह योजना झज्जर सहित दक्षिण हरियाणा के 7 ज़िलों नामत: भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार व नूँह के लिये शुरू की गई है।
- राज्य के किसानों को यह लाभ दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने के लिये दिया जाएगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है।
- योजना की जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार किसानों की लागत को कम करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है।
- राज्य में खरीफ फसल 2022 के दौरान एक लाख एकड़ में दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना के अंतर्गत दलहनी फसलें (मूंग व अरहर) को 70,000 एकड़ क्षेत्र में और तिलहन फसल (अरंड व मूंगफली) को 30,000 एकड़ में बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन व तिलहन की फसल उगाने वाले किसान को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने वाले किसान को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण कराना ज़रूरी है। वित्तीय सहायता फसल के सत्यापन के उपरांत किसानों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति, 2022-25

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही 'हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति, 2022-25' लागू करेगी। इससे प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को गति मिलेगी, साथ ही एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में जहाँ प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टेट ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के पाँचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा को एमएसएमई के क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय कार्यों के लिये सम्मानित किया था।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की उद्योगों को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता के कारण ही हरियाणा की 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस', 'ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स' और 'एक्सपोर्ट रेडीनेस' में उत्कृष्ट रैंकिंग आई है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, निर्यात तैयारी सूचकांक (भूमि बंद श्रेणी), 2021 में राज्य को पहला तथा 'लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेटस सर्वे, 2021' में दूसरा स्थान मिला है।
- दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार की हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति, 2020, एमएसएमई नीति, 2019 हरियाणा कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 आदि कई ऐसी नीतियाँ हैं, जिनसे राज्य के एमएसएमई को बहुत लाभ हुआ है और युवाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में हरियाणा सत्रहवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में हरियाणा पूरे देश में सत्रहवें स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में हरियाणा 661 स्कोर के साथ सत्रहवें स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

पशुओं के नस्ली विकास के लिये हरियाणा ब्राज़ील के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा

चर्चा में क्यों ?

6 जुलाई, 2022 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जे.पी. दलाल ने राज्य में ब्राज़ील के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिये एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जे.पी. दलाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ब्राज़ील दौरे पर है। ब्राज़ीलिया शहर में इस प्रतिनिधिमंडल ने गिर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करने के बाद बताया कि ब्राज़ील के गिर एसोसिएशन ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से हरियाणा राज्य से मुर्रा भैंस जर्मप्लाज़्म के आयात के लिये इच्छा जताई है।

नोट :

- बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एबीसीजेड के सदस्यों के साथ हरियाणा में गिर पशुओं के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की और जानकारी हासिल की।
- प्रतिनिधिमंडल ने ब्राज़ीलिया के पास अलेक्जेंड्रिओ ज़िले में मोटम गिर हट फार्म का दौरा किया, जो कि 1500 से अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली गिर गायों वाले सबसे बड़े गिर फार्म में से एक है।
- प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रजनन, पोषण और कृषि प्रबंधन प्रेक्टिस में पालन की जा रही, डेयरी प्रथाओं की जानकारी ली गई और उनका अध्ययन किया गया।
- जे.पी. दलाल ब्राज़ील के कृषि, पशुधन और आपूर्ति मंत्रालय के व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध सचिव जीन मार्सेल फर्नांडीस से डेयरी विकास और पशुओं की नस्लों के सुधार के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमत हुए। इसमें सूचनाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान, एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी (ईटीटी) और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) जैसी तकनीकों के संयुक्त अनुसंधान का आदान-प्रदान तथा आनुवंशिक सामग्री और जर्मप्लाज़्म का आदान-प्रदान शामिल हैं।
- उन्होंने जुइज डे फोरा में एंब्रापा पशु डेयरी (एंब्रापा गाडो डी लेइट) अनुसंधान केंद्र का भी दौरा किया और सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा भी की।

चरखी दादरी को मिली करीब 1100 करोड़ रुपए की सौगात

चर्चा में क्यों ?

8 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चरखी दादरी ज़िले को करीब 1100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, उनमें करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे निमड़-बडेसरा पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी शामिल है।
- कस्बा बौंद में महाविद्यालय का नया भवन बनाने की मांग भी उन्होंने पूरी की है। इस कॉलेज की बिल्डिंग निर्माण पर 16 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत आएगी।
- मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सिरसली जलघर, 5 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बने दादरी फायर स्टेशन, करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार दादरी-महेंद्रगढ़ रोड का उद्घाटन भी किया।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनी हड़ौदी माईनर, 2 करोड़ रुपए की लागत से बने छपार-रामपुरा लिंक रोड, 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनी लोहारू फीडर व गाँव सांवड़ में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया।

पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन करेगी हरियाणा सरकार

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में बाबा माखन शाह लबाना व बाबा लक्खी शाह बंजारा जयंती समारोह में पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसके बनने के बाद समाज की सभी समस्याओं की चिंता यह आयोग भी करेगा। आयोग के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उन सब वर्गों के कल्याण के लिये अलग से आयोग अथवा बोर्ड का गठन किया है, जो किन्हीं कारणों से प्रगति की दौड़ में पीछे रह गए हैं।

नोट :

- मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और गरीबों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिये सरकार ने 300 से अधिक स्कीमें चलाई हुई हैं। इनका लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिये प्रदेश में 117 अंत्योदय भवनों एवं लगभग 20 हज़ार अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से 47 विभागों की 618 सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
- इस अवसर पर मनोहर लाल खट्टर ने नगर पालिका कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर को लक्खी शाह बंजारा के नाम से बनवाने की घोषणा भी की।

हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2022 में स्वर्ण सहित जीते 3 पदक

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2022 को फिनलैंड के टांपरे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2022 में हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीनियर सिटीज़न कैटेगिरी में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में महज 74 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता, वहीं शॉटपुट में भी दो कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं।
- उल्लेखनीय है कि भगवानी देवी इससे पहले भी कई पदक जीत चुकी हैं। इन्होंने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किये थे, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2022 के लिये क्वालीफाई किया गया था।
- गौरतलब है कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1975 में की गई थी। इस चैंपियनशिप में 35 साल से ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। शुरुआत में केवल 5 एज ग्रुप को शामिल किया गया था, लेकिन अब 12 एज ग्रुप में स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं।
- पहला एज ग्रुप 35 साल से ऊपर आयु वर्ग का है। दूसरा 40 साल से ऊपर, तीसरा 45 साल से ऊपर, चौथा 50 साल से ऊपर, 5वाँ 55 साल से ऊपर, 6वाँ 60 साल से ऊपर, 7वाँ 65 से ऊपर, 8वाँ 70 साल से ऊपर, 9वाँ 75 साल से ऊपर, 10वाँ 80 साल से ऊपर, 11वाँ 85 साल से ऊपर और 12वाँ 90 साल से ऊपर का है।

पैक्स की कार्यप्रणाली को किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड

चर्चा में क्यों ?

11 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक (हरको) की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने की दिशा में निर्णय लेते हुए पैक्स की कार्यप्रणाली को चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटराइज्ड करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि हरको बैंक की शाखा प्रदेश के हर ज़िले में खोलने की संभावना तलाशी जाए। इसके लिये यदि नियमों में संशोधन करना पड़े तो किया जाए।
- वर्तमान में हरको बैंक की चंडीगढ़ तथा पंचकूला में दो ही जगह शाखाएँ हैं, बाँकि यह बैंक ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं का नियंत्रण रखता है।
- बैठक में बताया गया कि पैक्स का सीधा हरको बैंक से लिंक नहीं होता। प्रदेश में लगभग 700 पैक्स हैं, जो ग्रामीण स्तर पर बनी हुई हैं।
- वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि पंचकूला ज़िले की कनौली पैक्स में पूरा कार्य कंप्यूटराइज्ड हो चुका है और 62 अन्य पैक्स को कंप्यूटराइज्ड करने की प्रक्रिया जारी है। 30 नवंबर, 2022 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स के कर्मचारियों का वेतन भी सेंट्रलाइज किया जाए और सरकार की तरफ से इसकी व्यवस्था की जाए। पैक्स पर एकाधिकार को खत्म करने के लिये इसी की तर्ज़ पर गाँव में पढ़े-लिखे युवा किसानों से बातचीत कर ग्रामस्तर पर ग्राम कृषि प्राथमिक सहकारी समितियाँ (वैक्स) बनाई जाएँ और इनका पंजीकरण को-ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाए और किसान ही इन वैक्स का संचालन करें।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को तीन किस्तों में- खेत तैयार करने के लिये बीज, जुताई व खाद के साथ-साथ मज़दूरी देने के समय फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाए। ऋण रिकवरी को कटाई सीजन से जोड़ा जाए, ताकि किसान अपनी फसल बेचकर समय पर ऋण की अदायगी कर सकें। समय पर अदायगी करने वाले किसानों को एक प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के तहत स्वीकृत आवेदनों पर तत्परता से ऋण उपलब्ध करवाए जाएँ।

एचसीएस प्री की परीक्षा में चार के बजाय पाँच विकल्प होंगे

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2022 को हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने 24 जुलाई को होने वाली एचसीएस प्री की परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिये परीक्षा की ओएमआर शीट में चार के बजाय पाँच विकल्प करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि आयोग की ओर से 24 जुलाई, 2022 को एचसीएस प्री के 156 पदों के लिये परीक्षा ली जानी है।
- आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को नए ऑप्शन के साथ-साथ ओएमआर शीट और परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन भी जारी की है।
- अब अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर गोला खाली नहीं छोड़ सकेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है और वह विकल्प ए, बी, सी तथा डी को खाली छोड़ता है, तो उसे पाँचवा गोला (हैज-#) अनिवार्य रूप से भरना होगा।
- सिख धर्म से संबंधित युवकों को कड़ा और कृपाण ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन ऐसे युवकों को परीक्षा के रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले सेंटर पर पहुँचना होगा, ताकि उनकी स्क्रीनिंग हो सके कि कहीं कोई डिवाइस उनके पास न हो। अगर किसी के पास कोई प्रतिबंधित उपकरण मिलता है, तो उन्हें परीक्षा से रोक दिया जाएगा, जब तक हॉल में सभी ओएमआर शीट एकत्रित नहीं की जाती, तब तक कोई अभ्यर्थी कमरे से बाहर नहीं जा सकेगा।
- गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में एचपीएससी के उप-सचिव अनिल नागर व उसके दो साथियों को विजिलेंस ने लाखों रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। इन पर डेंटल सर्जन की भर्ती और एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे थे। उप-सचिव के पास ही गोपनीय शाखा की पूरी ज़िम्मेदारी थी और वह परीक्षा के बाद ओएमआर शीट में गड़बड़ी करके अभ्यर्थियों को पास कराता था। आयोग ने दोनों ही भर्तियों को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था।

हरियाणा सरकार ने किया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुरूप हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति दर्शन सिंह (सेवानिवृत्त) इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा, पूर्व कुलपति डॉ. एस.के. गक्खड़, श्याम लाल जांगड़ा और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के महानिदेशक इस आयोग के सदस्य, जबकि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष सचिव मुकुल कुमार सदस्य सचिव के तौर पर नियुक्त किये गए हैं।

नोट :

- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (2016 का 9) की धारा 3 की उप-धारा-1 तथा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।
- उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित कार्यों का निर्वहन करते समय आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करने, सरकार में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों और स्कीमों का अध्ययन करने, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों से विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध लाभों का आकलन करने, पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिये उपलब्ध रोज़गार अवसरों का अनुमान लगाना और रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने के लिये उपायों की सिफारिश करने का कार्य करेगा।
- इसके अलावा आयोग पिछड़े वर्गों के युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिये सामयिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किये जाने के लिये अध्ययन करना और सिफारिश करने जैसे कार्य करेगा। साथ ही, ऐसे उपायों का भी अध्ययन कर सिफारिश करेगा, जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लिये आवश्यक हो।
- गौरतलब है कि 10 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन करने की घोषणा की थी, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों और संबंधित जातियों को हर प्रकार की सुविधा एवं लाभ देने के उदेश्य से कार्य करेगा।

रोहतक में 500 एकड़ में बनेगा 'फुटवियर-लेदर' क्लस्टर

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एमएसएमई के अधिकारियों व फुटवियर इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में कहा कि राज्य के अधिक-से-अधिक युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार रोहतक में लगभग 500 एकड़ में 'फुटवियर-लेदर' क्लस्टर बनाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोहतक शहर के आस-पास के आईटीआई संस्थानों के विद्यार्थियों को फुटवियर इंडस्ट्री से जोड़कर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि लेदर इंडस्ट्री के उद्योगपतियों को स्थानीय स्तर पर ही कुशल युवा मिल सकें और युवाओं को उनके घर के नज़दीक रोज़गार हासिल हो सके।
- उप-मुख्यमंत्री ने फुटवियर इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगपतियों को काफी सहूलियतें दे रही है, ताकि उनको अपना उद्योग चलाने में कोई परेशानी न हो, इससे स्थानीय युवाओं को भी रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे।
- रोहतक में बनने वाले 'फुटवियर-लेदर' क्लस्टर में उद्योगपतियों को हर प्रकार से मदद की जाएगी। करीब दो दर्जन उद्योगों के चालू होते ही वहाँ पर एक साल में कॉमन सर्विस सेंटर बना दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को अपने कार्य में आसानी हो सकेगी।
- उन्होंने बताया कि राज्य में 'लेदर-इंडस्ट्री' के उद्योगपतियों की मदद के लिये लेदर से संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने 'फुटवियर-लेदर' क्लस्टर के पास ही लेबर हॉस्टल बनाने का आश्वासन भी दिया, ताकि वहाँ काम करने वाले मज़दूरों को रहने व इंडस्ट्री तक आने-जाने में परेशानी न हो।
- उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जहाँ प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 'स्टेट ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस' के पाँचवें संस्करण में हरियाणा को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में स्थान मिला है।
- हरियाणा सरकार की उद्योगों को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की प्रतिबद्धता के कारण ही हरियाणा की ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट रेडीनेस में उत्कृष्ट रैंकिंग आई है। इसके अतिरिक्त, निर्यात तैयारी सूचकांक (भूमि बंद श्रेणी)-2021 में राज्य को पहला तथा 'लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे-2021' में दूसरा स्थान मिला है।

नोट :

ब्राज़ील के सहयोग से हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिये उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2022 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जे.पी. दलाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं पशुओं की नस्ल सुधार के लिये हिसार में ब्राज़ील के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा कि स्वदेशी नस्ल की गायों के विकास हेतु एम्ब्रापा, ब्राज़ील के सहयोग से हरियाणा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ जेबू ब्रीडर्स (एबीसीजेड) से गिर जर्मप्लाज़्म (वीर्य/भ्रूण) का आयात किया जाएगा।
- इसके अलावा ब्राज़ील की एक ज़ीनोमिक्स कंपनी एल्टा जेनेटिक्स को गुणवत्ता वाले मुर्राह जर्मप्लाज़्म के निर्यात की संभावनाएँ तलाशी जाएंगी।
- हरियाणा में कृषि क्षेत्र में व्यापार के अवसर तलाशने हेतु इंडो-ब्राज़ीलियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को निमंत्रण दिया गया है। राज्य में डेयरी विकास एवं देसी पशु नस्लों के सुधार के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को और अधिक मज़बूत करने के अलावा एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलोजी (ईटीटी) और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) जैसी प्रौद्योगिकियों का संयुक्त अनुसंधान और आदान-प्रदान भी होगा।
- मंत्री ने कहा कि पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिये कनाडा की कंपनी द्वारा राज्य में एक सेंटर भी खोला जाएगा, जिसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल ज़ल्द ही हरियाणा का दौरा करेगा और उसके पश्चात् एक समझौता ज्ञापन होगा।
- अपने ब्राज़ील दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री जे.पी. दलाल ने बताया कि वर्ष 1911 में भावनगर के राजा ने गिर नस्ल की गायों को दानस्वरूप ब्राज़ील को दिया था और उसके बाद ब्राज़ील ने इन गायों की नस्ल सुधार में काम किया गया।
- गौरतलब है कि ब्राज़ील में गिर गाय की नस्ल में सुधार कर गिरलैंडो नस्ल को तैयार किया गया है, जो औसतन 15 लीटर दूध देती है, जिसमें 99 प्रतिशत जेनेटिक्स भारत की गिर गाय के पाए जाते हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने किया उचाना नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद ज़िले के उचाना नागरिक अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित होने से उचाना तथा आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर एवं सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त होंगी। इस ऑक्सीजन प्लांट में प्रति मिनट 250 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जो आपातकालीन स्थिति में मरीज़ों के उपचार के लिये राहत देगी।
- गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान उचाना जैसे इलाकों में ऑक्सीजन की कमी से मरीज़ों को परेशानी हुई थी। अब भविष्य में इसका स्थाई समाधान हो गया है।
- ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना से गंभीर बीमारियों से पीड़ित एवं इमरजेंसी के मरीज़ों को अब पीजीआई रोहतक या अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में जाने के जोखिम से भी राहत मिलेगी और उनको त्वरित उपचार भी मिलेगा।
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के अंतर्गत सीएसआर के सौजन्य से 45 लाख रुपए लागत से निर्मित इस ऑक्सीजन प्लांट के बेसमेंट एवं शैड आधुनिक स्तर पर श्रेष्ठ एवं नवीनतम टेक्नोलोजी के आधार पर बनाए गए हैं।

नोट :

- आधुनिक तकनीक से बनाए गए इस प्लांट से पाइपलाईनों के द्वारा अस्पताल के प्रत्येक बेड को कनेक्ट किया गया है, जिस पर आपातकालीन मरीज़ों को अस्पताल के सभी 30 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा निःशुल्क मुहैया होगी।
- इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता निरंतर 50 बेडों पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की है। इसके अलावा हर 24 घंटे में ज़रूरत के अनुसार 55 बड़े, यानी जंबो सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

हरियाणा मे ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क ने 'दुर्घटनारहित हरियाणा में युवाओं का दायित्व' विषय पर ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया। यह वेबिनार श्रृंखला 4 सितंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन परिवहन विभाग की पहल पर शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।
- नवदीप विर्क ने कहा कि पुलिस विभाग के सकारात्मक योगदान से विभाग ने सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिये सड़क सुरक्षा पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के श्रृंखलाबद्ध वार्षिक आयोजन किये हैं। यह पहल विश्व कीर्तिमान के रूप में लिम्का बुक रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हुई है।
- कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि अगला वेबिनार 27 जुलाई, 2022 को विषय 'सड़क सुरक्षा में स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका' पर होगा और इस वेबिनार में सभी पीजीआई एवं नर्सिंग के शिक्षक/विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
- 10 अगस्त, 2022 को विषय 'जीवन की रक्षा होगी तभी रक्षाबंधन त्योहार होगा' पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी आईटीआई के शिक्षक शामिल होंगे।
- 22 अगस्त, 2022 को विषय 'सड़क सुरक्षा जागरण अभियान में कलाओं की भूमिका' पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी मास कम्युनिकेशन एवं कला विभाग के शिक्षक हिस्सा लेंगे।
- इसी प्रकार 31 अगस्त, 2022 को विषय 'पर्यावरण संरक्षण में यातायात प्रबंधन की भूमिका' पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के वैज्ञानिक तथा शोधार्थी हिस्सा लेंगे।
- 4 सितंबर, 2022 को विषय 'सड़क सुरक्षा में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका' पर वेबिनार होगा, जिसमें सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हिस्सा लेंगे।

हरियाणा में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ गुरुग्राम से प्रदेश में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- नितिन गडकरी ने 3450 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें गुरुग्राम से सोहना तक ऐलिवेटेड हाईवे, एनएच-11 पर रेवाड़ी से अटेली मंडी चारमार्गीय सड़क तथा खेरड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालुवास गाँव तक चार लेन परियोजना शामिल हैं।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हरियाणा में लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। 1015 किमी. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे तथा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है। यह एक्सप्रेस वे गुरुग्राम ज़िला में सोहना से शुरू होता है।

नोट :

- गडकरी ने कहा कि अगले 5 साल में पेट्रोल के प्रयोग को वाहनों में समाप्त करने के लिये ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार 50 हज़ार ई-बस देने की योजना भी बना रही है। हरियाणा भी इसी तर्ज पर ई-बस शुरू करे। ई-बस का 41 रुपए 25 पैसे प्रति किमी. का खर्च आता है। इससे पेट्रोल व डीज़ल से होने वाला प्रदूषण कम होगा।
- नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकें, क्योंकि पराली से ईंधन बनता है। पराली की 2 हज़ार रुपए प्रति टन की कीमत मिलेगी और उससे बिटूमिन बनेगा, जिसे खरीदने के लिये एनएचएआई तैयार है।
- उन्होंने इथेनॉल के प्रयोग पर भी बल दिया और कहा कि हरियाणा में डीज़ल व पेट्रोल के पंप के स्थान पर इथेनॉल के पंप लगवाएँ और सभी इथेनॉल से गाड़ियाँ चलाएँ। इससे वाहन चालकों का आधा पैसा बचेगा और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।

नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इस इंडेक्स में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनवरी 2021 में जारी किये गए इंडेक्स में हरियाणा छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार हरियाणा तीन पायदान चढ़ते हुए शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया।
- नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं। ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (88 अंक) को शीर्ष स्थान मिला है। इस श्रेणी में दिल्ली (27.00 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) सबसे निचले पायदान पर है।
- नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिये एक व्यापक उपकरण है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिये उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है।
- इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिये एक हज़ार करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिये राज्य सरकार की एक हज़ार करोड़ रुपए की गारंटी को सात साल, यानी 1 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2029 तक के लिये रिन्यू करने का प्रस्ताव पेश किया था।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह सहकारी संस्था प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु किसानों को दीर्घकालीन ऋण निवेश उपलब्ध कराने में लगी है। इस तरह की क्रेडिट सीमा/ऋणों के लिये उन्हें नाबार्ड के डिबेंचर/ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। नाबार्ड सरकारी गारंटी पर यह सुविधा प्रदान करता है।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- संशोधन के अनुसार, 'आचरण नियम, 2016' के नियम 24 में वर्णित चल संपत्ति की परिभाषा में 'बीमा नीतियाँ' शब्द हटा दिया गया है। इसी प्रकार, अनुलग्नक-ए में 'बीमा नीतियाँ' शब्द जहाँ कहीं भी आएंगे, उन्हें हटा दिया गया है।
- राज्य सरकार ने 'चल संपत्ति' की परिभाषा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और 'आचरण नियम, 2016' के नियम 24 में वर्णित 'चल संपत्ति' की परिभाषा में संशोधन करने का निर्णय लिया।
- चल संपत्ति के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं को एक कर्मचारी द्वारा खुले बाज़ार में स्थानांतरित/बेचा जा सकता है, लेकिन 'बीमा नीतियाँ' किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को बेची/हस्तांतरण नहीं की जा सकती हैं। इसलिये, केवल 'चल संपत्ति' की अभिव्यक्ति से 'बीमा नीतियाँ' शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) की दोदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को लेकर आयोजित दोदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई-विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नज़र आएगी।
- उन्होंने कहा कि ई-विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी, यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी। इससे कागज़ की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हरियाणा की विधानसभा ही नहीं, बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के काम-काज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के काम-काज से तुलना भी कर सकेंगे।
- विधानसभा में पेश किये जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि सभी टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होंगे।

परिवार पहचान-पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

22 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र की ऑनलाइन सेवा लॉन्च की। इसके माध्यम से अब पात्र व्यक्ति महज़ एक क्लिक से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनवा सकेंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ऑनलाइन सेवा की लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) में रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। यह परिवार 'सरल' पोर्टल के माध्यम से अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका इनकम वेरीफिकेशन अभी बाकी है और यदि उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र चाहिये तो वे सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन को तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनका इनकम वेरीफिकेशन करवाया जाएगा और जल्द-से-जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि सरल पोर्टल से उपलब्ध होने वाले पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र पर एडीसी के हस्ताक्षर होंगे।

159 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यस्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई, जिसमें 159 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों का जोखिम कम करने और कृषि व्यापार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के लिये क्रियान्वित की जा रही योजनाओं हेतु अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमति प्रदान की गई है।
- इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि की उच्च तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
- मुख्य सचिव ने प्रदेश में मक्का उगाने वाले किसानों को 2400 रुपए प्रति एकड़ तथा दलहन फसलों के लिये 3600 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंज़ूरी दी। इससे प्रदेश में तिलहनी और दलहनी फसलों को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अलावा फसल विविधीकरण के लिये50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि किसान परंपरागत खेती के अलावा फसल विविधीकरण अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत कर सकें।
- फसल विविधीकरण के लिये प्रदेश के 10 ज़िलों में डेंचा, मक्का और दलहनी फसलों को बढ़ावा हेतु 50 हज़ार एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण की योजनाएँ क्रियान्वित की जाएंगी।
- उन्होंने कहा कि फसल चक्र बदलने से भूजल के गंभीर दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी और मिटी स्वास्थ्य में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों में भी बढ़ोतरी की जाए, ताकि भूमिगत जलस्तर में सुधार हो सके।
- मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिये पोर्टल बनाया गया है। किसान स्वेच्छा से पोर्टल पर अपलोड कर अपनी कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। इस वर्ष झज्जर, रोहतक, सोनीपत के किसानों की 20 हज़ार एकड़ भूमि को जलभराव समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
- उन्होंने बताया कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मृदा की जाँच की जा रही है और किसानों को भूमि की गुणवत्ता अनुसार खाद, बीज आदि का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये 100 मृदा जाँच लेबोरेट्री संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से अब तक 25 लाख सैंपल लिये गए हैं तथा किसानों, किसान सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदर्शन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं।

नोट :

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2022 को यूएसए के ओरेगन प्रांत के यूजीन में संपन्न वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) के फाइनल में हरियाणा के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

प्रमुख बिंदु

- नीरज चोपड़ा ने चैंपियनशिप के फाइनल के चौथे राउंड में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक अपने नाम किया। जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने दूसरे राउंड में 90.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
- नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.39 मीटर का थ्रो किया। दूसरी ओर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले और दूसरे प्रयास में क्रमश: 90.21 और 90.46 मीटर का थ्रो करते हुए अपना मेडल पक्का कर लिया।
- नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 86.37 मीटर का थ्रो जबकि चौथे राउंड में 88.13 मीटर का थ्रो करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। नीरज का यह ओलिंपिक से भी बेहतर प्रदर्शन था। उन्होंने टोक्यो ओलिंपिक में 87.58 मीटर का थ्रो करते हए गोल्ड मेडल जीता था।
- इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले साल 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में काँस्य पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनीं थीं।
- गौरतलब है कि हाल ही में हुई स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज और एंडरसन की टक्कर हुई थी, तब एंडरसन ने 90.31 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जबकि नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सिल्वर मेडल जीता था।
- इसी साल दोहा डायमंड लीग में तो एंडरसन पीटर्स ने 93.07 मीटर दूर तक भाला फेंककर सबको चौंका दिया था। एंडरसन इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरे थे। उन्होंने पिछली बार 2019 में 86.89 मीटर दूर थ्रो करते हुए गोल्ड जीता था।
- गौरतलब है कि हरियाणा अपने खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक में पदक जीतने पर देश में सबसे ज्यादा पुरस्कार और सुविधाएँ देता है।
- हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये सुरक्षित रोज़गार सुनिश्चित करने हेतु 'हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018' बनाए हैं।
- हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल एवं युवा मामले विभाग ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिये 10 डे-बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियाँ शुरू की हैं।

प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये खोली जाएंगी 1200 लाइब्रेरी

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिये आधुनिक सुविधाओं से लैस 1200 लाइब्रेरी खोली जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा दिलाने के उद्देश्य से ये आधुनिक लाइब्रेरी खोली जा रही हैं।

नोट :

- उन्होंने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव पिरथला, फतेहपुरी, रसूलपुर, चांदपुरा, ललुवाल व हिंदवाला में ई-लाइब्रेरी एवं आधुनिक जिम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
- ये वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी पानी, नवीनतम कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड सहित सभी सुविधाओं से लैस हैं। इसी तरह आधुनिक जिम में भी अच्छी तकनीक की मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में किया पुलिस के 'स्मार्ट ई-बीट सिस्टम'का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई-पहल की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में 'स्मार्ट ई-बीट सिस्टम' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम की विवरिणका भी जारी की और इस सिस्टम से जुड़े पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

- मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में स्मार्ट पुलिसिंग के प्रयास के तहत ई-बीट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे बीट सिस्टम भी डिजिटलाइज्ड हो गया है।
- यह एक ऐप आधारित सिस्टम है। बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी की हाजिरी भी इस ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनीटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी।
- यह एक जीआईएस आधारित सिस्टम है, जिसके शुरू होने से इनकी मॉनीटरिंग ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो पाएगी। उसके बाद उनकी लोकेशन की मॉनीटरिंग आसानी से की जा सकेगी।
- यह नई प्रणाली गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी 33 पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करेगी। इनमें 119 मोटरसाइकिल राइडर तैनात होंगे और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर दो पुलिसकर्मी होंगे।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने शहर में 2056 संवेदनशील लोकेशन अथवा बिंदुओं की पहचान की है, जिनमें मुख्य रूप से एटीएम, पेट्रोल पंप, वरिष्ठ नागरिक के निवास स्थान, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अपराध प्रभावित क्षेत्र आदि शामिल हैं।
- इस सिस्टम को भविष्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि फोन नंबर 112 पर मिलने वाली कॉल पर ईआरवी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिये पहुँच सके।
- ई-बीट सिस्टम पर प्रेजेंटेशन देते हुए गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने बताया कि पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ईस्ट गुरुग्राम तथा मानेसर क्षेत्र में लागू किया गया था। उसमें सामने आई कमियों को दूर करते हुए इसी महीने इस ई-बीट सिस्टम का विस्तार कर इसे साउथ गुरुग्राम तथा वेस्ट गुरुग्राम में भी लागू किया गया है।

हरियाणा ई-अधिगम टैबलेट वितरण योजना की उज्बेकिस्तान ने की सराहना

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2022 को चंडीगढ़ में उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री कंवर पाल को बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ई-अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट, 2 जीबी इंटरनेट डाटा व सॉफ्टवेयर दिये जाने की उज्बेकिस्तान सहित विश्व भर में प्रशंसा हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान उज्बेकिस्तान के नामनगान विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य सदस्यों ने इस योजना की विस्तृत जानकारी ली तथा शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि उन्हें हरियाणा इस प्रकार की योजना तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करे, ताकि वे भी अपने देश में विद्यार्थियों के लिये ऐसी योजना लागू कर सकें।

नोट :

- कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूल स्तर पर बच्चों को टैबलेट देकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गहरी रुचि का परिचय दिया है। स्कूल में बच्चे ई-अधिगम योजना के माध्यम से पढ़ाई कर टेक्नोलॉजी में कुशल होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार भी उपलब्ध होंगे।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने सरकारी स्कूलों के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किये गए हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिये सुपर-100 कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों का करियर बनाने के लिये शिक्षा विभाग का सुपर-100 कार्यक्रम एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत आईआईटी व नीट की फ्री कोचिंग दी जाती है।
- उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उनके देश के विद्यार्थियों में भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित कौशल विकास की रुचि पैदा हो, इसके लिये वे इस योजना का अनुसरण कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर भी विशेषज्ञ तैयार हों।
- प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अब भारत ने नई शिक्षा नीति-2020 बनाई है, लेकिन उनके यहाँ पर अब तक रशियन पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है, यह उचित समय है कि अब भारत की इस नीति से अधिक-से-अधिक सीखा जाए।
- शिक्षा मंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान के लिये आग्रह करते हुए कहा कि उज्बेकिस्तान के 5 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अंग्रेज़ी विषय में हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों में दाखिला करवाया जाए, जिससे वहाँ के विद्यार्थी अंग्रेज़ी विषय पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकें।
- प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत में अंग्रेज़ी भाषा पाठ्यक्रम आसान है, इसलिये भारतीय अंग्रेज़ी भाषा की सामग्री उनके स्कूलों के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा, अंग्रेज़ी व कंप्यूटर विषय के अध्यापकों को लघु प्रशिक्षण हेतु उज्बेकिस्तान भेजने पर भी शिक्षा मंत्री ने सहमति जताई है।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा कला व संस्कृति के लिये प्रसिद्ध फरीदाबाद सूरजकुंड मेले का उज्बेकिस्तान पार्टनर देश है। इसके सहयोग से मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ-साथ शिक्षा में हरियाणा उज्बेकिस्तान का सहयोगी बनेगा।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया। उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को वहाँ के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों द्वारा डिज़ाइन की गई टोपी व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति-2022

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई के माध्यम से टेक्सटाइल उद्योग को भी बढ़ावा देने तथा अधिक-से-अधिक युवाओं को रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में जल्द ही 'हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति-2022' लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी नई दिल्ली में 'हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति-2022' के प्रारूप को लेकर आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक के बाद दी।
- बैठक में 'हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति-2022' के लक्ष्य, उद्यमिता विस्तार, निवेश, रोज़गार सृजन, अनुदान, टेक्सटाईल पार्क व अन्य संदर्भित विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' के संदर्भ में भी विमर्श हुआ।
- उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 'हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति-2022' के प्रारूप पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया है। अब इस नीति को अनुमोदन के लिये मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- वर्ष 2025 तक की समयावधि के लिये तैयार की गई इस नीति से करीब 4 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश तथा 20 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने का अनुमान है।
- इस नीति के अंतर्गत टेक्निकल टेक्सटाइल को विशेषरूप से प्रोत्साहित कर विस्तार दिया जाएगा। सिंथेटिक फाईबर व रिजेनरेटेड फाईबर ईकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना भी इस नीति में शामिल किया गया है।

नोट :

पैक्स उपभोक्ताओं के लिये शीघ्र ही एकमुश्त योजना

चर्चा में क्यों ?

27 जुलाई, 2022 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने सहकारी समितियाँ व हरको बैंक के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा केंद्रीय सहकारी बैंक की तर्ज़ पर पैक्स उपभोक्ताओं के लिये भी शीघ्र ही एकमुश्त अदायगी योजना बनाई जाएगी, ताकि पैक्स उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी पैक्स को जल्द-से-जल्द कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। प्रदेश की 751 पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। पहले चरण में 307 पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। दूसरे चरण में शेष पैक्स को भी कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि नाबार्ड पायलेट प्रोजेक्ट के तौर कंप्यूटराइज्ड पैक्स का मुआयना करेगा, इसलिये पैक्स का डाटा अपलोड कर उन्हें जल्द ऑनलाईन करने का कार्य किया जाए। इसके लिये शीघ्र ही पंचकूला में कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- प्रदेश की केंद्रीय सहकारी बैंक उपभोक्ताओं के लिये क्रियान्वित एकमुश्त अदायगी योजना के तहत अब तक 28.09 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। सहकारी बैंकों के 24397 सदस्य हैं, जिनमें से 1207 सदस्यों ने एकमुश्त अदायगी योजना का लाभ उठाया है।

हरियाणा सरकार 2023 में बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल' के रूप में प्रचारित करेगी

चर्चा में क्यों ?

28 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल'के रूप में प्रचारित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय 'न्यूट्री-सेरिअल'वर्ष घोषित किया है।
- हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है तथा उत्पादन भी प्रति एकड़ लगभग 8 क्विंटल तक होता है।
- बैठक में मुख्य सचिव ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिये सीधे कंपनियों से अनुबंध खेती करवाने के प्रयास करें।
- बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई कि हैफेड संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व अन्य अरब देशों के साथ बासमती चावल का निर्यात पहले से ही कर रहा है।
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में जौ की अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को अधिक-से-अधिक प्रेरित किया जाए। इसके अलावा कपास की फसल पर संभावित 'पिंक वार्म'के प्रकोप से बचाने के लिये भी त्वरित अभियान चलाया जाए।
- बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी 2007-08 से आरंभ किया था। इसके तहत दलहन एवं तिलहन की पैदावार को बढ़ावा देना था। वर्ष 2018-19 में खाद्य तेल एवं पाम ऑयल को भी इसमें शामिल किया गया है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिये 4013.86 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रमाणित बीज, क्लस्टर प्रदर्शन खेत, माइक्रोन्यूट्रेंट, कृषि मशीनरी, समेकित कीट प्रबंधन तथा फसल एवं मृदा सुरक्षा प्रबंधन के लिये सब्सिडी दी जाती है।

नोट :

वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका 'वित्त विभाग बुलेटिन' जारी

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त विभाग द्वारा तैयार पुस्तिका 'वित्त विभाग बुलेटिन' जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तिका का उद्देश्य हरियाणा सरकार के सभी विभागों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को सुविधाजनक बनाना और उन्हें सतत् विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिये मानदंड प्रदान करना है।
- इस बुलेटिन में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य के बजट आवंटन के साथ-साथ सतत् विकास लक्ष्यों के विभिन्न संकेतकों में ज़िलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी शामिल किया गया है।
- इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने कहा कि यह दस्तावेज़ एक एकल डिपॉजिटरी के इरादे से संकलित किया गया है, जहाँ वित्त विभाग द्वारा जारी सभी निर्देश और अधिसूचनाएँ एकसाथ एक स्थान पर मिल सकेंगी।

'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022' को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2022' की स्वीकृति के संबंध में एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत उचित मूल्य की दुकान जारी करने के लिये 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम-से-कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिये दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिये एक गाँव को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। गाँव के 300 से कम राशन कार्ड के लिये भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- उचित मूल्य की दुकान पर विक्रय यंत्र बिंदु के माध्यम से पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के बाद आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
- नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने का हकदार होगा। राशन दुकान की सेवाओं को ऑनलाइन या अन्य तंत्र के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

हरियाणा एसडीजी ज़िला सूचकांक-2022 जारी

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ज़िलों के मध्य प्रगति के मूल्यांकन के लिये 'हरियाणा एसडीजी ज़िला सूचकांक-2022' जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- 'हरियाणा एसडीजीसीसी ज़िला सूचकांक-2022' को वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने तैयार किया है।
- रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएनडीपी शोको नोडा ने कहा कि ज़िला सूचकांक ज़िलों की प्रगति के मूल्यांकन करने का एक मेनफ्रेम साधन है और इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का संचार करते हुए एसडीजी की प्राप्ति हेतु एविडेंस-ड्राइन कार्रवाई के लिये इनपुट प्रदान करता है।
- इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि एसडीजी एक्शन एजेंडे में ज़िलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने विभिन्न एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्त करना जारी रखा है।

नोट :

- एसडीजी के नोडल संस्थानों के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग और राज्य स्तर पर स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने ज़िलों के बीच सहयोगात्मक गति के लिये आवश्यक प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 को एक प्रोविजनल ज़िला सूचकांक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। यह संबंधित विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार किया गया दूसरा और अपडेट संस्करण है और यह 115 संकेतकों, 62 लक्ष्यों एवं 15 गोल्स पर आधारित है।
- हालाँकि, यह दूसरी रिपोर्ट भी सभी संबंधितों के परामर्श के लिये एक अंतरिम रिपोर्ट है। इस दस्तावेज़ को सभी हितधारकों, मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजा जाएगा।
- अंतिम दस्तावेज़ मार्च 2023 में टिप्पणियों, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के बाद अन्य रिपोर्टों के साथ लॉन्च किया जाएगा।
- यह दस्तावेज़ प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और आउट फील्ड अधिकारियों के लिये एसडीजी लक्ष्यों और विज़न 2030 को प्राप्त करने की दिशा में काम करने हेतु एक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में काम करेगा। एसडीजी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किये गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- इस इंडेक्स में अंबाला ने 74 के स्कोर के साथ शीर्ष ज़िले के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी। गुरुग्राम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पंचकूला, करनाल और यमुनानगर तालिका में तीसरे स्थान पर हैं। फरीदाबाद छठे स्थान पर है, कुरुक्षेत्र और सिरसा सातवें स्थान पर हैं।
- लक्ष्य 4 और 6 में 'फ्रंट रनर'की संख्या सबसे अधिक है, जबकि लक्ष्य 8 में सबसे अधिक 'आकांक्षी'हैं।
- एसडीजी 4, एसडीजी 10 और एसडीजी 11 में, हरियाणा का स्कोर 'परफॉर्मर'श्रेणी से 'फ्रंट रनर'श्रेणी में आ गया है।

गोल के अनुसार टॉप ज़िले	
लक्ष्य 1: गरीबी नही	गुरुग्राम
लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी	अंबाला
लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण	कैथल और जींद
लक्ष्य 4: गुणवत्तायुक्त शिक्षा	गुरुग्राम
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता	चरखी दादरी
लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और सफाई	रोहतक
लक्ष्य 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	अंबाला
लक्ष्य 8 : अच्छा काम और आर्थिक विकास	गुरुग्राम
लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा	गुरुग्राम
लक्ष्य 10: कम असमानता	यमुनानगर
लक्ष्य 11: सतत् शहर और समुदाय	सिरसा
लक्ष्य 12: ज़िम्मेदार खपत और उत्पादन	कुरुक्षेत्र
लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई	यमुनानगर
लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन	यमुनानगर
लक्ष्य 16: शांति, न्याय और मज़बूत संस्थाएँ	पंचकूला

नोट :

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के परिवारों/दिव्यांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में संशोधित नीति/निर्देशों को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर, 2021 की घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बल (सेना, नौसेना और वायु सेना) जो युद्ध/ऑपरेशनल क्षेत्र में, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं आदि में मारे गए/दिव्यांगकर्मियों के लिये निशक्तता के आधार पर अनुग्रह अनुदान की दरों में वृद्धि की है।
- संशोधित दरों के अनुसार, दिव्यांग सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) को 75 प्रतिशत या अधिक निशक्तता के मामले में 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। इससे पूर्व यह राशि 15 लाख रुपए थी।
- इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 25 लाख रुपए तथा 25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक निशक्तता के मामले में 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि क्रमशः 10 लाख और 5 लाख रुपए थी।

दृष्टि The Vision

नोट :